BROOKINGS INDIA

SAMBANDH

क्षेत्रीय संबंद्धता पहल

नीति–संक्षिप्त । जनवरी 2020

रणनीति के रूप में ‘संबंध’

क्षेत्रीय संबंधों के लिए भारत का नया दृष्टिकोण

कॉन्स्टेंटिनो जेवियर

प्रतिलिप्याधिकार © 2020

ब्रूकिंग्स संस्थान भारत केंद्र
नंबर 6, दूसरी मंजिल, डॉ जोस पी रिज़ल मार्ग,
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली – 110021

अनुशंसित उद्धरण:

जेवियर, कॉन्स्टेंटिनो। "रणनीति के रूप में संबंध: क्षेत्रीय संबंधों के लिए भारत का नया दृष्टिकोण। ब्रुकिंग्स इंडिया नीति–संक्षिप्त 012020-01, जनवरी 2020| ब्रूकिंग्स संस्थान भारत केंद्र।

आईएसबीएन 978-81-941963-7-2

ब्रुकिंग्स संस्थान भारत केंद्र, भारत और विश्व के सामने आने वाले अवसरों और चुनौतियों पर अत्याधुनिक, स्वतंत्र, नीति–प्रासंगिक अनुसंधान और विश्लेषण हेतु मंच के रूप में कार्य करता है। यह केंद्र नई दिल्ली में स्थित है, और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत शेयरों द्वारा सीमित, गैर लाभ कंपनी के रूप में पंजीकृत है। 2013 में स्थापित, यह केंद्र वाशिंगटन, डीसी आधारित ब्रुकिंग्स संस्थान का तीसरा और नवीनतम विदेशी केंद्र है। हमारा कार्य ब्रुकिंग्स के "गुणवत्ता। स्वतंत्रता। प्रभाव" के आदर्श वाक्य पर आधारित है।

संपूर्ण विषयवस्तु लेखक (लेखकों) के व्यक्तिगत विचारों को दर्शाती है। ब्रूकिंग्स इंडिया किसी भी विषय पर संस्थागत दृष्टिकोण नहीं रखता है।

ब्रूकिंग्स इंडिया के लिए सुनैना दलाया द्वारा संपादित

इस शोधपत्र का हिन्दी अनुवाद बाहरी संस्था द्वारा ब्रुकिग्स संस्थान भारत केन्द्र के लिए किया गया है।

नीति–संक्षिप्त। जनवरी 2020

रणनीति के रूप में 'संबंध'

क्षेत्रीय संबंद्धता के लिए भारत का नया दृष्टिकोण

कॉन्स्टेंटिनो जेवियर

*लेखक इस शोधपत्र और 'संबंध' पहल पर अपनी टिप्पणियों के लिए शिवशंकर मेनन, ध्रुव जयशंकर, रिया सिन्हा और निधि वर्मा को धन्यवाद देता है।

PASS

सार–संक्षेप

यह नीति–संक्षिप्त, दक्षिण एशिया के प्रति भारत के नए दृष्टिकोण को प्रेरित करने वाले भू–रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों का परीक्षण करता है। मुख्य रूप से चीन के उदय के प्रत्युत्तर में ''नेबर हुड फर्स्ट'' (पड़ोसी देशों को वरीयता देने) की नीति के अंतर्गत, नई दिल्ली ने क्षेत्रीय संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। यद्यपि भारत अब इस क्षेत्र के साथ पुनः संपर्क स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन वित्तीय क्षमता, अधिकारी वर्ग समन्वय, और परियोजना कार्यान्वयन के संबंध में महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं। इसके अतिरिक्त, यह सार–संक्षेप ब्रूकिंग्स इंडिया की क्षेत्रीय संबंद्धता पहल 'संबंध' के विषय में परिचय कराता है, जो पूरे उपमहाद्वीप में विद्वानों और और एकीकरण के अभ्यासकर्ताओं से प्राप्त होने वाली सहयोगात्मक जानकारी पर निर्भर है। यह पहल दक्षिण एशिया और भारत–प्रशांत क्षेत्र के साथ भारत का संपर्क पुनः स्थापित करने में रूचि रखने वाले नीति निर्माताओं और हितधारकों के लिए अनुभवजन्य अंतर्दृष्टियों एवं अनुशंसाओं का समावेश करती है।

परिचय

राजनीतिक विभाजनों, आर्थिक मतभेदों और भू–रणनीतिक विचलनों के इतिहास से चिह्नित भारतीय उपमहाद्वीप एकीकरण के असामान्य रूप से कम स्तर के साथ अभी भी अत्यधिक खंडित है। कोई अन्य क्षेत्रीय शक्ति अपने निकटतम पड़ोसी देशों से उतनी असंबद्धित नहीं है जितना कि भारत। इस असंबद्धता को भारत के आर्थिक और सुरक्षा हितों के लिए चुनौती मानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में इस क्षेत्र में आंतरिक रूप से संबद्धता और इस क्षेत्र की अपने निकटवर्ती क्षेत्रों के साथ संबद्धता, दोनों को ही नीतिगत प्राथमिकता दी। सिंगापुर में 2018 की शांगरी–ला वार्ता में भारत–प्रशांत क्षेत्र के महत्व पर बोलते हुए उन्होंने दश की नई रणनीतिक अनिवार्यता पर जोर देते हुए कहा:

"संबद्धता महत्वपूर्ण है। यह [केवल] व्यापार और समृद्धि को बढ़ाने की तुलना में कहीं अधिक अर्थ रखती है। यह क्षेत्र को एकजुट करती है। भारत सदियों से विभिन्न व्यापार मार्गों के मिलन बिन्दुओं पर रहा है। हम संबद्धता के लाभों को समझते हैं। इस क्षेत्र में कई संबद्धता पहल हैं। यदि इन्हें सफल होना है, तो हमें अनिवार्य रूप से न केवल अवसंरचना का निर्माण करना चाहिए, अपितु परस्पर विश्वास का निर्माण भी अवश्य करना चाहिए।"[1]

दक्षिण एशिया के भीतर, मोदी सरकार ने क्षेत्रीय संबंद्धता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का संकेत देने हेतु नेबरहुड फर्स्ट (पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की) नीति का निर्माण किया है। शीत युद्ध की अधिकतर अवधि के दौरान रणनीतिक पृथकता और उपेक्षा की नीति, और उसके बाद क्षेत्रवाद को अनिच्छापूर्वक अपनाए जाने के कारण, भारत की क्षेत्रीय नीति का ध्यान अब सीमा पार संबंधों को मजबूत करने की दिशा में अपरिवर्तनीय रूप से स्थानांतरित हो गया है। अब तक की गई प्रगति महत्वपूर्ण (आगे समीक्षा की गई है) और यहां तक कि अभूतपूर्व रही है, जिसमें नई पाइप लाइन बिछाने, विद्युत नेटवर्क का निर्माण करने, समुद्री पत्तन, रेल और हवाई अड्डे की अवसंरचना का उन्नयन, और लोगों के मध्य आदान–प्रदान को पुनर्जीवित करने सहित अनेक कार्य सम्पन्न किए गए हैं। लेकिन, विभिन्न मोर्चों पर ऐसी असाधारण प्रगति के बावजूद, दिल्ली की क्षेत्रीय सक्रियता और महत्वाकांक्षा अपनी ही सफलता से भ्रमित भी हो चुकी है, जिससे कार्यान्वयन में हुई कमी उजागर होती है। कई दशकों तक क्षेत्रीय अंतर्मुखता और नीतिगत ठहराव के बाद नई सरकार और निजी हितधारक, समन्वय और निष्पादन में आने वाली चुनौतियों को उजागर करते हुए जमीनी स्तर पर अधिकाधिक संबंद्धता संभव करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इन चुनौतियों में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि संबंद्धता के लिए प्रेरणा हेतु भारत सरकार की विभिन्न शाखाओं (केंद्र और राज्यों दोनों में) से गुणवत्तापूर्ण डेटा, इनपुट साथ ही निजी क्षेत्रक, विभिन्न घरेलू क्षेत्रों और यहां तक कि पड़ोसी देश से संलग्नता की आवश्यकता होती है।

क्षेत्रीय संबंद्धता के लिए भारत के नए दृष्टिकोण, के प्रमुख प्रेरक तत्वों, अब तक की गई प्रगति और सामना की गई चुनौतियां की जांच के बाद, इस सार संक्षिप्त का अंतिम खंड 'संबंध' के लिए शोध कार्य–सूची (एजेंडा) प्रस्तुत करता है। यह कार्यक्रम ब्रूकिंग्स इंडिया में एक नई पहल है जो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका सहित पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों का मानचित्रण करने के लिए डेटा–संचालित अनुसंधान संपन्न करती है। 'संबंध', संबंद्धता की समग्र समझ से प्रेरित होकर, आर्थिक, पर्यावरण, राजनीतिक, सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक संकेतकों में भारत के क्षेत्रीय एकीकरण का सर्वेक्षण करता है। यह पहल भारत को दक्षिण एशिया और भारत प्रशांत क्षेत्र के साथ पुन: संबंद्ध करने में रुचि रखने वाले नीति निर्माताओं और हितधारकों के लिए अनुभवजन्य अंतर्दृष्टि तथा अनुशंसाओं का योगदान करती है।

असंबंद्धता की स्थिति

देखा जाए तो भारत आज विश्व के सबसे कम एकीकृत क्षेत्र में स्थित है। सभ्यतागत और औपनिवेशिक एकीकरण की अवधियों की तुलना में, विभाजनों के इतिहास से भारतीय उपमहाद्वीप अब विखंडित–सा हो गया है। यद्यपि, यहां तक कि यूरोप के ऐतिहासिक राष्ट्र राज्यों के मध्य भी राष्ट्रीय सीमाएं हमेशा राजनीतिक इंजीनियरिंग का परिणाम रही हैं, लेकिन दक्षिण एशिया में विभाजन की राजनीतिक रेखाएँ विशेष रूप से समस्याग्रस्त हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों, आर्थिक स्थानों, नृजातीय भाषायी समूहों से होकर गुजरती हैं।

दूसरी ओर, समय के साथ बदलते सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों के आधार पर क्षेत्र भी लचीले निर्माण हैं। यूरोपीय संघ शायद सबसे उन्नत क्षेत्रीय निर्माण है— इसकी राजनीतिक और संस्थागत संगठन भौगोलिक निकटता, साझे मूल्यों, और सर्वनिष्ठ बाजार और मुद्रा सहित यूरोपीय परंपराओं को परिलक्षित करती है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का

1 Ministry of External Affairs (2018, June 1). Prime Minister's keynote address at Shangri La Dialogue. Retrieved from https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/29943/Prime+Ministers+Keynote+Address+at+Shangri+La+Dialogue+June+01+2018

संघ (ASEAN) क्षेत्रीय निर्माण का एक और उदाहरण है। 1950 के दशक में, यह अकल्पनीय था कि आसियान (ASEAN) के 10 देश भौगोलिक और संगठनात्मक पहचान की सर्वनिष्ठ भावना के आधार पर एक दिन मूल्यों को साझा करेंगे। फिर भी आज हम "दक्षिण पूर्व एशिया" के साथ साझा आर्थिक स्थितियों और यहां तक कि राजनयिक स्थितियों की बात करते हैं, जिसे "आसियान कार्यप्रणाली" के रूप में संदर्भित किया जाता है।

इनकी और 1960 के दशक के बाद से उभरे मजबूत क्षेत्रवाद के अन्य उदाहरणों की तुलना में, एक क्षेत्र के रूप में दक्षिण एशिया की बात करना क्या अभी भी अर्थ रखता है? 1950 के दशक के बाद से आधी सदी से अधिक के राजनीतिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक विखंडन के इतिहास को देखते हुए, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान और श्रीलंका को एकजुट रखने वाली, "क्षेत्रीयता" की किस प्रकार की समझ अभी भी विद्यमान है? इस चुनौती पर अपने विचार व्यक्त करते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2019 में स्वीकार किया कि अब जबकि "क्षेत्रवाद ने विश्व के हर कोने में जड़े जमा ली हैं।........... [यदि] हम इस दृष्टि से पीछे रहे हैं तो इसका कारण यह है कि दक्षिण एशिया में अन्य क्षेत्रों की भाँति सामान्य व्यापार और संबंद्धता नहीं है।"[2]

वास्तव में, भारत और उसके पड़ोसियों के मध्य "असंबद्धता", सामान्यतः बनी रहने वाली स्थिति बनी हुई है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2014 में आसियान क्षेत्र में अंतर–क्षेत्रीय व्यापार की हिस्सेदारी 30% रही जबकि दक्षिण एशिया में यह 5% तक जितनी अत्यधिक कम थी।[3] पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1,500 किलोमीटर लंबी सीमा पर स्थित म्यांमार के साथ भारत का भूमि आधारित व्यापार, सुदूर मध्य अमेरिका में अवस्थित निकारगुआ के साथ भारत के कुल व्यापार जितना ही है।[4] यह तीन गुना सस्ता भी है दिल्ली से सिंगापुर तक किसी कंटेनर को समुद्री परिवहन के माध्यम से भेजने में उतना ही समय लगता है जितना समय पड़ोस के बांग्लादश स्थित ढाका तक के लिए लगता है।[5]

संबद्धता की यह दयनीय स्थिति आज भू–रणनीतिक विचलन, राजनीतिक राष्ट्रवाद, और आर्थिक संरक्षणवाद की कई दशकों तक अपनाई गई नीति को प्रतिलक्षित करती है।

परिवहन संबंद्धता के संदर्भ में, भारत और नेपाल या म्यांमार के मध्य कोई यात्री रेल लिंक नहीं है।[6] 1960 के दशक में लगभग दर्जन भर भारत–बांग्लादेश रेल लिंक थे जबकि 2000 के दशक के मध्य में इनकी संख्या मात्र 1 रह गई।[7] श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के लिए उड़ानों के अतिरिक्त, भारत ने 1980 के दशक में इस द्वीप के अन्य भागों के लिए अन्य सभी यात्री हवाई, रेल और जहाज लिंक बंद कर दिए। इस क्षेत्र के भीतर उड़ान भरने की तुलना में दुबई या बैंकॉक जैसे अन्य क्षेत्रों के लिए उड़ान भरना प्रायः अधिक आसान होता है: नेपाल और पाकिस्तान के मध्य कोई सीधी उड़ान नहीं है, और 2007 तक दिल्ली और ढाका के मध्य केवल एक नॉन–स्टॉप लिंक था।

संबंद्धता की यह वर्तमान दयनीय स्थिति दशकों तक अपनाई गई भू–रणनीतिक विचलन, राजनीतिक राष्ट्रवाद और आर्थिक संरक्षणवाद की नीतियों को प्रतिलक्षित करती है। ब्रिटिश शासन के अंत और दक्षिण एशिया में नए स्वतंत्र राज्यों के उदय के साथ, यह क्षेत्र 1950 के दशक के बाद विखण्डित हो गया। भारत ने इस विखण्डन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई: इसने संप्रभुता और नागरिकता की कठोर क्षेत्रीय परिभाषा, निरंकुश शासन पर आधारित संरक्षणवादी आर्थिक मॉडल, और गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को अपनाया, जिसने पड़ोस को वैश्विक घटनाक्रमों से अछूता रखा।

2 Ministry of External Affairs (2019, September 27). Statement by external affairs minister at the informal meeting of SAARC Council of Ministers (CoM) on the sidelines of 74th UNGA.

3 Sanjay Kathuria (2018). A glass half full: The promise of regional trade in South Asia. Washington, D.C.: International Bank for Reconstruction and Development/World Bank. Retrieved from https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30246/9781464812941.pdf?sequence=8&isAllowed=y

4 Export-Import Bank of India (2017, February). India's engagements with CLMV: Gateway to ASEAN markets, Occasional paper no. 180. Retrieved from https://www.eximbankindia.in/Assets/Dynamic/PDF/Publication-Resources/ResearchPapers/Hindi/69file.pdf. Also, data for Nicaragua from India's Ministry of Commerce from http://commerce.nic.in/eidb/default.asp.

5 Shipping a full container 20'ST- 1 m from Delhi to Other BIMSTEC Capital Cities (Yangon in the Case of Myanmar), based on Sea Rates (2017, August). Retrieved from https://www.searates.com/

6 Karishma Singh (2017, June 15). Nepal revamps colonial-era railway line. Reuters. Retrieved from https://www.aol.com/article/news/2017/06/15/nepal-revamps-colonial-era-railway-line/22287945/

7 Shohel Mamun (2017, April 5). Government to restore rail links to India, Nepal, Bhutan. Dhaka Tribune. Retrieved from http://www.dhakatribune.com/bangladesh/foreign-affairs/2017/04/05/govt-restore-rail-links-india-nepal-bhutan/

क्षेत्र के अधिपति के रूप में भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ अधिकतर आर्थिक संबंध विच्छेद कर लिए, साथ ही साथ इस क्षेत्र से परे जुड़ने के पड़ोसियों के प्रयासों का विरोध भी किया, चाहे वह चीन (नेपाल) या दक्षिण पूर्व एशिया (श्रीलंका) हो। इसलिए, जहाँ विश्व ने आर्थिक निर्भरता के आधार पर 1960 के दशक के बाद क्षेत्रवाद की अभूतपूर्व अवधि देखी, वहीं भारत ने स्वयं को पड़ोस से असंबद्ध करने का विडंबनापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया। शीत युद्ध की अधिकतर अवधि के दौरान, दिल्ली की नीति नए संबंध स्थापित करने के स्थान पर पहले से स्थापित संबंधों को समाप्त कर स्वयं को और अपने पड़ोसियों को बाहरी प्रभाव से पृथक करने के लिए बाधाएँ खड़ी करने की थी।

दृष्टिकोण विद्यमान रहा। इसलिए 2006 में विदेश सचिव के रूप में सेवा करते हुए, श्याम सरन ने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों को परिधि पर स्थित क्षेत्रों या आंतरिक मुख्य भूमि में प्रवेश को रोकने के लिए 'बफर जोन' के रूप में कार्य करने वाले क्षेत्रों के रूप में देखने के दृष्टिकोण को तत्काल परिवर्तित करने की अपील की।''[9]

सीमा क्षेत्रों को "हमें किसी न किसी प्रकार बाहरी विश्व के प्रभाव से बचाने वाली अभेद्य दीवारों के रूप में देखने की सीमावर्ती चौकी की मानसिकता'' के स्थान पर सरन ने जोर दिया कि भारतीय हितों की सर्वोत्तम उपलब्धि अपने पड़ोसियों के साथ ''पारस्परिकता का ताना–बाना बुनने ... तथा हमारी आर्थिक समृद्धि में हिस्सेदारी देने [जिन्हें अनिवार्य रूप से अवसर दिया जाना चाहिए] से संभव होगी।''[10]

भू–रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रेरक तत्व

"संबंद्धता" शब्द हाल ही में भारत के नवीनतम भू–रणनीतिक मूलमंत्र के रूप में उभरा है, जिसे जापान, आसियान या यूरोपीय संघ सहित कई रणनीतिक भागीदारों के साथ व्यापार, हवाई यातायात और डेटा में पहल सहित सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भों में उपयोग किया जाता है। हालांकि, इस अवधारणा का सबसे अधिक उपयोग भारत के निकटतम क्षेत्र के संदर्भ में किया जाता है। भारत के कूटनीतिक एजेंडे पर टिप्पणी करते हुए, एस जयशंकर ने दक्षिण एशिया को "प्राथमिकता के पहले चक्र" में रखा और इस बात पर जोर दिया कि ''पड़ोस को प्राथमिकता देने की नीति वाणिज्य के बारे में है, संपर्कों के बारे में है।''[8] यद्यपि इसे अब एक अभूतपूर्व प्राथमिकता के रूप में उजागर किया गया है, लेकिन क्षेत्रीय संबंद्धता के लिए रणनीतिक तर्क 1980 के दशक के समय का है, जिसमें 1985 में और विशेष रूप से 1991 के बाद क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ (SAARC) का निर्माण सम्मिलित है, जब भारत ने बाजार सुधारों को अपनाया और एक के बाद एक आने वाली सरकारों ने पड़ोसी देशों के साथ पारस्परिक आर्थिक निर्भरता को आगे बढ़ाया।

हालांकि, यहां तक कि 2000 के दशक के मध्य में, आर्थिक उदारीकरण सुधारों के एक दशक से अधिक समय के उपरांत भी, सरकार के कुछ भागों में पुराना पृथकतावादी

> "आपकी [पड़ोस] नीति हितों की ऐसी विविध श्रृंखलाओं को स्थापित करती है जो देशों को आपस में एकजुट करती हैं। इसलिए, भले ही राजनीतिक परिवर्तन हों, संबंध को निश्चित स्थिरता प्रदान की जाती है, क्योंकि ये पारस्परिक निर्भरताओं के कुछ बहुत मजबूत प्रकार हैं, चाहे वे आर्थिक पक्ष में हो, चाहे नदी जल साझा करने की शर्तों में हो, चाहे यह हमारी ऊर्जा संबंधी पारस्परिक निर्भरता की शर्तों में हों।"[11]

रणनीतिक अनिवार्यता के रूप में संबंद्धता के विषय में सरन की भविष्यद्दर्शी अभिव्यक्ति ने धीरे–धीरे नीति निर्माण परिमंडलों में अपना महत्त्व स्थापित किया, लेकिन उनके विचार 2000 के दशक के अंत में भारत की आर्थिक मंदी और दिल्ली की पहलों के विरुद्ध पाकिस्तान द्वारा सार्क के माध्यम से निरंतर उत्पन्न किए जा रहे अवरोधों से घिर गए थे।

2014 में घोषित, पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति पुनः स्थापित हुई लेकिन अब पहली बार संपूर्ण सरकार में व्यापक रूप से साझा किए जाने वाले तथा आधारभूत हित के रूप में परिभाषित किए इस दृष्टिकोण को भी प्राथमिकता दी गई कि: संबंद्धता नई सर्वसम्मति है। आगे तीन कारकों की चर्चा की गई है जो इस नए भारतीय प्रोत्साहन को आकार प्रदान करते हैं और संबंद्धता के लिए मूलमंत्र हैं।

8 Ministry of External Affairs (2019, September 17). Transcript of press conference by external affairs minister on 100 days of government.

9 Ministry of External Affairs (2006, September 9). Does India have a neighbourhood policy? – Talk by foreign secretary at ICWA. Retrieved from https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/2342/Does+India+have+a+Neighbourhood+Policy++Talk+by+Foreign+Secretary+at+ICWA+September+9+2006

10 Ibid.

11 Ibid.

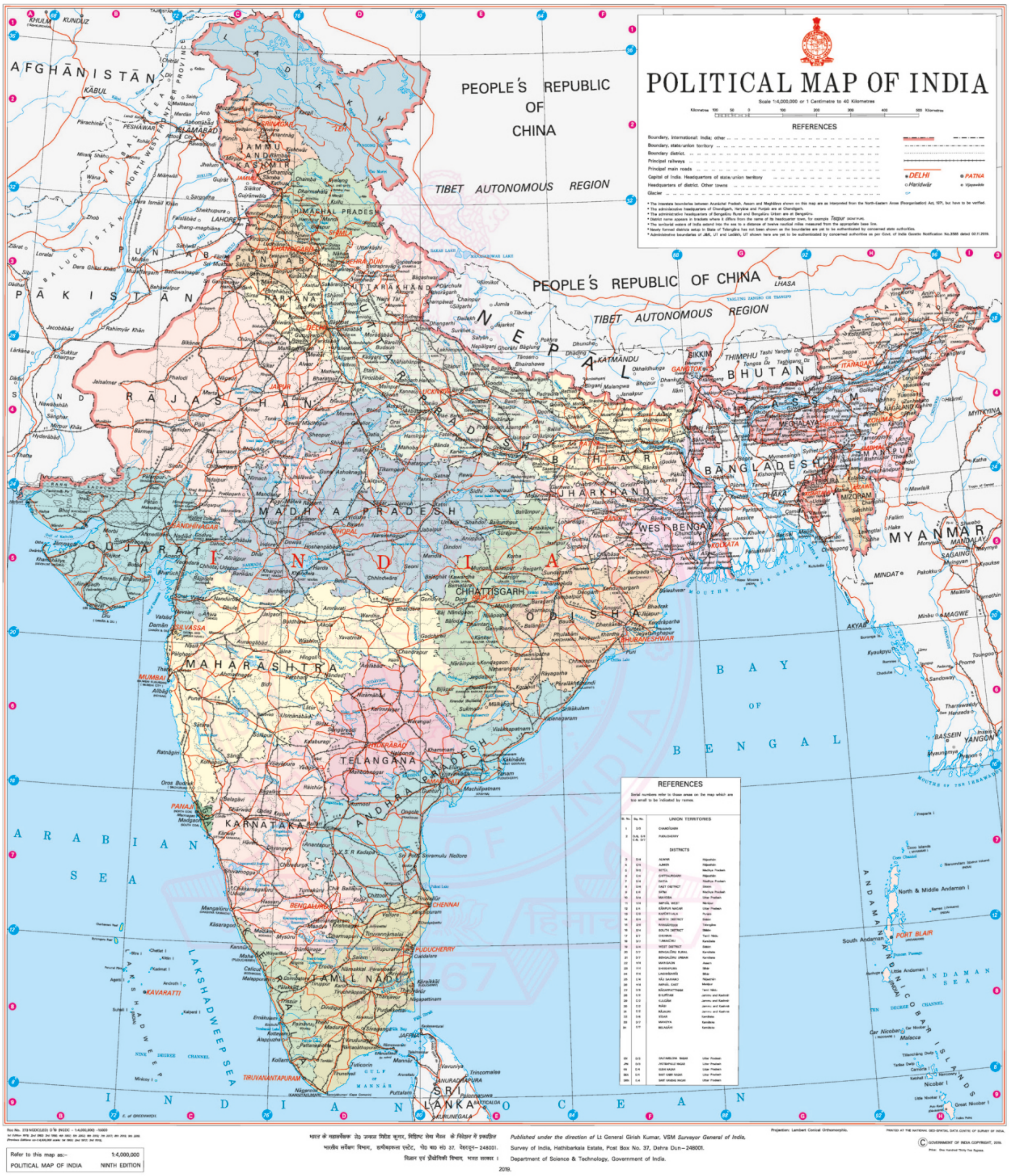

स्रोत: भारत का सर्वेक्षण, भारत सरकार

1. नई संबंद्धता नीति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक तत्व चीन के प्रति भू–रणनीतिक अनुक्रिया और संपूर्ण उपमहाद्वीप से इसका अभूतपूर्व संबंध है। जो कभी भारत का प्रभाव क्षेत्र था उसमें घुसपैठ करते हुए बीजिंग ने दक्षिण एशिया में अपनी राजनयिक, आर्थिक और राजनीतिक उपस्थिति का बड़े पैमाने पर विस्तार किया है।

बीजिंग ने अवसंरचना वित्तपोषण एवं विकास में विशेष रुचि ली है। एकमात्र भूटान को छोड़कर भारत के सभी अन्य पड़ोसी देशों ने 'बेल्ट एंड रोड पहल' (BRI) में भागीदारी की है।

पिछले कुछ वर्षों में चीन की आर्थिक उपस्थिति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है जो कई क्षेत्रकों में भारत की पारंपरिक प्रधानता से प्रतिस्पर्धा करती है। 2018 में, इस क्षेत्र में चीनी व्यापार 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जितना अधिक हो गया जो अपने पड़ोसियों के साथ भारत के वाणिज्यिक आदान–प्रदान की तुलना में पांच गुना अधिक है।[12] श्रीलंका में चीन का अब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 35% है, जो भारत की भागीदारी (16%) की तुलना में बहुत अधिक है।[13] एक चीनी कंसोर्टियम ने बांग्लादेश में ढाका स्टॉक एक्सचेंज का 25% अधिग्रहण करने के लिए भारत की तुलना में अधिक बोली लगाई।[14]

बीजिंग ने अवसंरचना वित्तपोषण एवं विकास में विशेष रुचि ली है। एकमात्र भूटान को छोड़कर भारत के सभी अन्य पड़ोसी देशों ने 'बेल्ट एंड रोड पहल' (BRI) में भागीदारी की है। श्रीलंका में हम्बनटोटा समुद्री पत्तन के लिए 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर में 99 वर्ष के पट्टे के लिए चीनी राज्य संचालित कंपनी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।[15] दूसरी ओर, नेपाल ने पहले ऑप्टिक फाइबर लिंक को चालू करना आरम्भ कर दिया है और हिमालय भर में नई सड़कों और रेलवे की योजना बना रहा है।

अंततः चीन ने भारत के पड़ोस में प्रभाव बढ़ाने के लिए अपनी सैन्य और कूटनीति का उपयोग करना भी आरम्भ कर दिया है। 2017 में नेपाल ने चीन के साथ पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया, यहां तक कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की जलसेना की पनडुब्बियों ने श्रीलंका में डॉक किया है और कथित तौर पर समुद्री डकैती विरोधी मिशनों के लिए हिंद महासागर में कई बार घुसपैठ की गई। पूरे दक्षिण एशिया में, सरकारी अधिकारियों, राजनीतिक दलों, विश्वविद्यालयों और मीडिया के मध्य नए क्षेत्रों का निर्माण करने के लिए चीनी दूतावासों द्वारा अब बलप्रयोग करने और दवाब बनाने के साधनों का उपयोग किया जा रहा है।

2. भारत की संबंद्धता नीति का दूसरा प्रेरक तत्व आर्थिक विकास और क्षेत्र में इसके बाजार का आकार और केंद्रीयता है। उपभोग के बढ़ते स्तर और अवसंरचना का आधुनिकीकरण दक्षिण एशिया के भूगोल को तेजी से संकुचित कर रहे हैं। इसके विपरीत, व्यापार में लगने वाला समय और लागत कम होने के साथ सीमा पार आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए प्रोत्साहन भी बढ़ रहे हैं। 2019 में 9% के अपेक्षित वृद्धि औसत सहित दक्षिण एशिया विश्व में सबसे तेजी से विकसित होता क्षेत्र बना हुआ है।[16] बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था केवल 10 वर्ष पहले की तुलना में अब तीन गुना बड़ी है, और भारत के अधिकांश अन्य पड़ोसियों ने 2008 के बाद से अपने सकल घरेलू उत्पाद को दोगुना कर लिया है।[17]

भारत के सीमावर्ती राज्य भारत की संबंद्धता नीति के इस आर्थिक प्रेरक तत्व का नेतृत्व कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, पूर्वोत्तर में भूटान ने असम की राजधानी गुवाहाटी में अपना पहला वाणिज्य दूतावास खोला,[18] और मेघालय और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों ने अब क्रमशः बांग्लादेश और म्यांमार के साथ मजबूत व्यापार, निवेश और अवसंरचना में सक्रिय रूप से रुचि दिखाई है।

12 World Bank, WITS Database https://wits.worldbank.org/countrysnapshot/en/CHN.

13 P. K. Balachandran (2017, December 14). China overtakes India as Sri Lanka's largest trading partner. The Citizen.. Retrieved from https://www.thecitizen.in/index.php/en/NewsDetail/index/5/12511/China-Overtakes-India-as-Sri-Lankas-Largest-Trading-Partner. Also see, https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/sri-lanka/investing-3.

14 Dhaka Stock Exchange sells 25 pct stake to Chinese Consortium (2018, May 15). Reuters. Retrieved from https://www.reuters.com/article/bangladesh-dhaka-stock/dhaka-stock-exchange-sells-25-pct-stake-to-chinese-consortium-idUSL3N1SM3ZX

15 Sri Lanka leased Hambantota port to China for 99 years. Now it wants it back (2019, November 30) Business Standard. Retrieved from https://www.business-standard.com/article/international/sri-lanka-leased-hambantota-port-to-china-for-99-yrs-now-it-wants-it-back-119112900206_1.html

16 World Bank (2018). South Asia Economic Focus, Spring 2018: Jobless growth?. Washington, D.C.: World Bank. Retrieved from https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29650?locale-attribute=en

17 Data for Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, Bhutan, Maldives (2019). Retrieved from https://data.worldbank.org/?locations=NP-BD-LK-MM-BT-MV

18 Bhutan opens consulate in Guwahati (2018, February, 2). The Hindu. Retrieved from https://www.thehindu.com/news/national/other-states/bhutan-becomes-second-country-to-open-consulate-in-guwahati/article22632607.ece

दक्षिण एशिया के आर्थिक विकास की कहानी और बढ़ती परस्पर निर्भरता ने, अधिक, बेहतर और तेज संबंद्धता प्रदान करने के लिए भारत पर अधिकाधिक दबाव डाला है। शीत युद्ध की अवधि के दौरान कई दशकों तक, भारत के श्रीलंका जैसे पड़ोसियों ने इस क्षेत्र में भारत की दबंग भूमिका से बचने का प्रयास किया; लेकिन आज वे चाहते हैं कि भारत संपर्कों को मजबूत करे और गतिशीलता की बाधाओं को कम करे। इस नई सक्रियता पर अपने विचार प्रतिबिंबित करते हुए, एस जयशंकर ने 2018 में कहा:

. ...हमारे पड़ोसियों में से हर एक आज हम पर विद्युत, विद्युत पारेषण, डीजल की आपूर्ति, सड़कों का निर्माण करने, रेलवे को अपने क्षेत्र में लाए जाने के लिए दबाव डाल रहा है, [तो] पड़ोस में [भारत के लिए] संबंद्धता की मांग है ... वे हमसे ऐसा करने की आशा–अपेक्षा करते हैं। ऐसा करना हमारे हित में है ... हमें उनकी ओर से प्रतिदान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, मेरा विचार है कि अपने हित के अनुकूल बड़ा क्षेत्र निर्मित करने के लिए पड़ोसियों से उदारतापूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। जब मैं अपने पड़ोसी के लिए निवेश करता हूँ तो मैं एक प्रकार से अपने लिए भी निवेश कर रहा होता होता हूँ।[19]

2014 के बाद संबंद्धता का तीसरा और अंतिम प्रेरक तत्व सांस्कृतिक दर्शन से आकार ग्रहण करता है जो भारत की प्राचीन काल की केंद्रीय भूमिका को सभ्यतागत शक्ति के रूप में पुनः सक्रिय करने का दावा करता है। उदाहरण के लिए, नेपाल की अपनी यात्राओं में, प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक संबंधों और साझा इतिहास और हिंदू विरासत पर बार–बार जोर दिया।[20] 2017 में उन्होंने बौद्ध वेसाक समारोह में भाग लेने के लिए विशेष रूप से श्रीलंका की यात्रा की, जहां उन्होंने दोनों देशों के मध्य संबंधों को "बौद्ध धर्म के हमारे पारस्परिक मूल्यों" पर आधारित होने के रूप में संदर्भित किया। [21]

मृदु शक्ति पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जैसी पहलों की मेजबानी करके, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) ने अग्रसक्रिय सार्वजनिक कूटनीति को भी आगे बढ़ाया है जो दक्षिण एशिया और उससे परे विस्तारित साझा सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों पर केंद्रित है।[22] ऊपर जांच किए गए भू–रणनीतिक और आर्थिक कारकों को पूरक के रूप में, संबंद्धता के लिए यह "भारतीय" दृष्टिकोण पूरे क्षेत्र में व्यक्ति से व्यक्ति के मध्य नए संपर्कों को सक्रिय करने के लिए प्रयासरत है।

इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का ध्यान संबंद्धता पर केंद्रित होने से इस क्षेत्र में सांस्कृतिक पुनर्मिलन हेतु समग्र खोज को भी स्वरूप मिला है जो इस विचार पर कि भारत की सभ्यता अपनी राजनीतिक सीमाओं से परे विस्तारित रही है।[23] इस विचार के एक समर्थक इंडिया फाउंडेशन के राम माधव ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले पांच प्रमुख स्तंभों में से संस्कृति को एक स्तंभ के रूप में परिभाषित किया है और यह तर्क दिया है कि पहले की तुलना में यह एक अंतर है।

“पहले हमारी विदेश नीति में संस्कृति और सभ्यता को कोई स्थान प्राप्त नहीं था। जबकि सभ्यता और संस्कृति भारत का मजबूत बिंदु हैं । हम अपनी सांस्कृतिक विचारधारा और सभ्यतापरक जीवन मूल्यों के आधार पर अन्य देशों के साथ और वैश्विक समुदाय के साथ मिलजुल कर कार्य करने की दिशा में अधिकाधिक आगे बढ़ रहे हैं।[24]

19 Doing foreign policy differently (2018, August 3). 24th Lalit Doshi Memorial Lecture by S. Jaishankar, Lalit Doshi Memorial Foundation, p. 21. Retrieved from http://ldmf.org.in/pdfs/LDMF%20Booklet%202018%20PDF%20File%20-%20Speech%20-%20Final.pdf

20 Nepal on top of India’s Neighbourhood First policy: Modi (2019, May 11). Hindu BusinessLine. Retrieved from https://www.thehindubusinessline.com/news/world/nepal-at-top-in-indias-neighbourhood-first-policy-modi/article23854228.ece

21 Press Information Bureau (2017, May 12). PM addresses opening ceremony of the International Vesak Day celebrations. Retrieved from https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=161734

22 See https://www.uscpublicdiplomacy.org/event/conference-indias-soft-power.

23 Ian Hall (2019). Modi and the reinvention of Indian foreign policy, Policy Press.

24 Jaideep Mazumdar (2017, September 2). Ram Madhav on Kashmir, North East, foreign policy and going back to the roots. Retrieved from https://swarajyamag.com/politics/swarajya-exclusive-ram-madhav-on-kashmir-north-east-foreign-policy-and-going-back-to-the-roots.

संबंद्धता को लागू करना: अभूतपूर्व प्रगति

भारत की नई क्षेत्रीय संबद्धता नीति किस प्रकार से कार्यान्वित की जाती रही है और हाल के वर्षों में इसकी क्या उपलब्धियां रही हैं। निस्संदेह, विविध प्रकार के क्षेत्रकों में प्रगति वृद्धिशील और असाधारण रही है, और बिल्कुल निकट के पड़ोसियों के साथ पुनः संपर्क स्थापित करने के लिए ऊर्जावान प्रयास (नीचे सूचीबद्ध) किए जा रहे हैं।

1. राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर, अपने पड़ोसी प्रतिभागियों तक पहुंचने के प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास अभूतपूर्व हैं। उन्होंने वर्ष 2014 और वर्ष 2019[25] में अपने दोनों ही शपथ ग्रहण समारोहों में क्षेत्रीय नेताओं को आमंत्रित किया, लगभग 40 वर्षों के बाद श्रीलंका के लिए द्विपक्षीय राज्य–यात्रा करने वाले मोदी प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री (यदि हम 1987 में सैन्य हस्तक्षेप पर मोहर लगाने के लिए राजीव गांधी द्वारा की गई छोटी सी यात्रा को छोड़ दें) बने।[26] वर्ष 2014 में वे लगभग 20 वर्षों में नेपाल का दौरा करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री भी बने। ऐसी राजनीतिक पहुंच का अनुकरण उनके कैबिनेट मंत्रियों द्वारा भी किया गया। उदाहरण के लिए, 2016 में मनोहर पर्रिकर 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद से उसका दौरा करने वाले प्रथम भारतीय रक्षा मंत्री बने।[27]

2. अवसंरचना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के साथ सीमाओं पर व्यापार और गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए एक दर्जन से अधिक एकीकृत चेक पोस्ट का निर्माण अथवा विस्तार किया जा रहा है।[28] नेपाल और बांग्लादेश के साथ अंतर्देशीय जलमार्ग समझौतों को चालू किया जा रहा है। बांग्लादेश के साथ रेलवे संपर्कों की संख्या 2008 में केवल एक थी जो अब वर्तमान में चार हो गई है और छह और अधिक संपर्कों की योजना बनाई जा रही है।[29] 2019 में भारत और नेपाल में दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार तेल पाइपलाइन का उद्घाटन किया।[30] और पहली बार हिमालय से भूटानी कार्गो एक भारतीय नदी पोत पर बांग्लादेश पहुंचा।[31]
कई वर्षों की देरी के बाद भारत ने अंततः अपने पूर्वी बंदरगाहों के माध्यम से नेपाली कार्गो के लिए सुगम पारगमन और निकासी प्रक्रियाओं की पेशकश की। भारतीय सहायता के साथ उन्नयन के बाद चार दशकों से अधिक समय के बाद उत्तरी श्रीलंका में जाफना में हवाई अड्डा दक्षिण भारत से सीधी उड़ान के साथ पुनः जुड़ा।[32] 2017 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा दक्षिण एशियाई उपग्रह के प्रक्षेपण ने पूरे क्षेत्र में डिजिटल संबंद्धता को बढ़ाया। और, एक नए शिपिंग समझौते के अंतर्गत, भारत और बांग्लादेश अब कोलंबो या अन्य और भी सुदूर स्थत बंदरगाहों में संपर्क करने के स्थान पर माल ढुलाई का सीधे आदान–प्रदान कर सकते हैं।

3. पडोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति, उल्लेखनीय अधिकारीतंत्र संबंधी और संगठनात्मक परिवर्तनों का कारण भी बनी है। पड़ोसी देशों के साथ कई द्विपक्षीय संयुक्त आयोग पुनः सक्रिय किए गए। उदाहरण के लिए नेपाल के साथ, 23 वर्ष बाद 2016 में द्विवार्षिक आयोग की पुनः बैठक हुई। द्विपक्षीय परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी के लिए दिल्ली ने अपने राजदूत और नेपाल के विदेश सचिव के मध्य एक द्विपक्षीय निरीक्षण तंत्र की भी स्थापना की, जिसकी केवल तीन वर्ष में सात बार बैठक हुई। 2019 में, विदेश मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रीय संबंद्धता पहलों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक नया भारत–प्रशांत क्षेत्र प्रभाग बनाया गया।

25 Bimstec leaders invited to PM Modi's oath-taking ceremony on May 30 (2019, 28 May). Hindustan Times. Retrieved from https://www.hindustantimes.com/india-news/bimstec-leaders-to-attend-pm-modi-s-swearing-in-ceremony-on-may-30-sources/story-8mqVN7k3rSpJ8xluJ9sCUP.html

26 PM Narendra Modi to be first Indian PM to visit Nepal in 17 years (2014, August 1). India Today. Retrieved from https://www.indiatoday.in/india/story/narendra-modi-to-visit-nepal-after-17-years-first-prime-minister-202543-2014-08-01

27 Dinakar Peri (2016, November 29). Parrikar in Dhaka to boost defence ties. The Hindu. Retrieved from https://www.thehindu.com/news/national/Parrikar-in-Dhaka-to-boost-defence-ties/article16720185.ece

28 Land Ports Authority of India (2018, July 18). Road map of ICP's. Retrieved from http://www.lpai.gov.in/content/innerpage/next-phase.php

29 India-Bangladesh rail links closed after 1965 war with Pakistan will reopen: Sheikh Hasina (2019, October 17). DD News. Retrieved from http://ddnews.gov.in/national/india-bangladesh-rail-links-closed-after-1965-war-pakistan-will-reopen-sheikh-hasina

30 Gopal Sharma (2019, September 10). India and Nepal open South Asia's first cross-border oil pipeline. Reuters. Retrieved from https://in.reuters.com/article/nepal-india/india-and-nepal-open-south-asias-first-cross-border-oil-pipeline-idINKCN1VV13P

31 First Indian cargo ship from Bhutan arrives in Bangladesh via India (2019, July 18). Times of India. Retrieved from http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/70280710.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

32 Meera Srinivasan (2019, October 12). Reconnecting Jaffna to Southern India. The Hindu. Retrieved from https://www.thehindu.com/news/international/reconnecting-jaffna-to-southern-india/article29667745.ece

और, राज्य स्तर पर असम सरकार ने हाल ही में अपना "एक्ट ईस्ट" प्रभाग आरम्भ किया।[33]

4. नए संस्थागत और बहुपक्षीय आयामों के साथ भी संबंद्धता को लागू किया जा रहा है। पाकिस्तानी व्यवधानों के कारण सार्क को प्राथमिकता की सूची से बाहर करने के बाद दिल्ली ने बहु–क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC) और बांग्लादेश– भूटान–भारत–नेपाल (BBIN) पहल सहित वैकल्पिक क्षेत्रीय संस्थानों को अपनाने के लिए व्यावहारिक रूप से कदम बढ़ाए। इस प्रकार की उपक्षेत्रीय सहयोग पहलें 1990 के दशक से अस्तित्व में है लेकिन 2016 के बाद ही सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हैं। कई वर्षों तक बहुपक्षीय वार्ताओं के बाद भारत ने 2017 में ट्रांसपोर्ट्स इंटरनेटेक्स राउटियर्स (TIR) पर भी हस्ताक्षर किए और पुष्टि की, जो क्षेत्र पर्यन्त और क्षेत्र के होकर अंतरराष्ट्रीय कंटेनर आवागमन को सुविधाजनक करती है।

5. भारत सरकार ने क्षेत्रीय संबंद्धता बढ़ाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन लागू किए हैं। भारतीय कंपनियों को पड़ोसी देशों में रणनीतिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए निविदा जीतने में सहयोग करने हेतु दिल्ली ने 2015 में एक नई रियायती वित्त योजना (CFS) की घोषणा की जिसे 2018 में नए सिरे से तैयार किया गया था।[34] सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BAPD) और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) के अंतर्गत, दिल्ली ने 17 सीमावर्ती राज्यों में महत्वपूर्ण अवसंरचना को विकसित करने हेतु अपने वित्तीय आवंटन का बड़े पैमाने पर विस्तार किया है और सीमा पार आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहनों में बढ़ोतरी की है।[35]

6. अंत में, दक्षिण एशिया में अपने पृथकतावादी रुख से दूर जाते हुए, भारत ने क्षेत्र के परे के प्रतिभागियों के साथ समन्वय और सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक नए भू–रणनीतिक दृष्टिकोण के माध्यम से संबंद्धता को भी आगे बढ़ाया है। उदाहरण के लिए, भारत ने जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक त्रिपक्षीय अवसंरचना वित्तपोषण समूह की स्थापना की। दिल्ली और टोक्यो संयुक्त रूप से श्रीलंका के कोलंबो में एक नया समुद्री पत्तन टर्मिनल बना रहे हैं।[36] भारत, एशियाई विकास बैंक (ADB) के साथ मिलकर पूर्वी तट के साथ और दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (SASEC) कार्यक्रम के एक भाग के रूप में एशिया की सबसे बड़ी मल्टीमॉडल संबंद्धता परियोजनाओं में से एक को लागू कर रहा है। बांग्लादेश में, भारत ने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को विकसित करने के लिए रूस के साथ अनुबन्ध किया है।[37]

यद्यपि भारत इस क्षेत्र में तीसरे देशों में सहयोग हेतु चीनी प्रस्तावों पर विचार करने के प्रति अनिच्छुक रहता है, लेकिन यह 'बेल्ट तथा रोड पहल' (BRI) हेतु वैकल्पिक संबंद्धता दृष्टिकोण विकसित करने हेतु "समान विचारधारा वाले" भागीदारों के साथ कार्य करने के लिए कहीं अधिक उत्साही रहा है। इसलिए 2018 में बोलते हुए, भारत के विदेश सचिव विजय गोखले ने बंगाल की खाड़ी में संबंद्धता के हितों को "भारत–प्रशांत क्षेत्र कहे जाने वाले विकास क्षेत्र के उप–समुच्चय'' के रूप में उल्लेख किया।[38]

कार्यान्वयन अंतराल को पाटना: रणनीतिक चुनौतियां

विभिन्न संबंद्धता आयामों में सरकार के अभूतपूर्व निवेश के परिणामस्वरूप भारत का कार्यान्वयन अंतराल बढ़ा है। "अधिकाधिक संबंद्धता" सरकार भर में प्रचलित आकर्षक आदेश है, लेकिन इसकी व्याख्या प्रायः अस्पष्ट रहती है और इसे संगठनात्मक और समन्वय संबंधी चुनौतियों के साथ ही साथ विभिन्न भू–आकृतिक, आर्थिक और राजनीतिक दबावों का सामना करना पड़ता है।

33 Government of Assam (2019, March 31). Act East policy. Retrieved from https://assam.gov.in/en/main/ACT%20EAST%20POLICY1

34 Press Information Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India, Cabinet approves extension of Concessional Financing Scheme (CFS) to support Indian entities bidding for strategically important infrastructure projects abroad. Retrieved from https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1541088

35 Press Information Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India (2019, July 16). Assistance under border area development programme. Retrieved from https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=191773

36 Sri Lanka, Japan, India sign deal to develop East Container Terminal at Colombo Port (2019, May 28). The Hindu. Retrieved from https://www.thehindu.com/news/international/sri-lanka-japan-india-sign-deal-to-develop-east-container-terminal-at-colombo-port/article27273794.ece

37 India to help build nuclear plant in Bangladesh (2019, March 2). The Hindu. Retrieved from https://www.thehindu.com/news/national/india-to-help-build-nuclear-plant-in-bangladesh/article22911756.ece

38 Ministry of External Affairs (2018, August 30). Transcript of media briefing by foreign secretary on BIMSTEC summit in Nepal. Retrieved from https://mea.gov.in/media-briefings.htm?dtl/30339/Transcript+of+Media+Briefing+by+Foreign+Secretary+on+BIMSTEC+Summit+in+Nepal+August+30+2018

तालिका 1:
क्षेत्र के साथ पुनः संपर्क स्थापित करना: महत्वपूर्ण पहलें

वर्ष	पहल
1985	बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका द्वारा क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ (सार्क) की स्थापना की गई। अफगानिस्तान 2007 में सार्क के आठवें सदस्य के रूप में सम्मिलित हुआ।
1987	भारत ने श्रीलंका के साथ अपने पहले प्रत्यक्ष आईएसडी टेलीफोन लिंक का उद्घाटन किया।
1993	ढाका में सार्क अधिमानी व्यापार व्यवस्था (SAPTA) हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद, 2004 में, एक दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता (SAFTA) किया गया।
1993	17 सीमावर्ती राज्यों में महत्वपूर्ण अवसंरचना विकसित करने के लिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) आरम्भ किया गया।
1996	उप–क्षेत्रीय सहयोग पर नए सिरे से ध्यान किया जाना, जिसमें गैर–पारस्परिकता के गुजराल सिद्धांत सम्मिलित हैं। बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल दक्षिण एशिया विकास चतुष्कोण (SAGQ) बनाते हैं।
1997	भारत हिंद–महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) और 'बहु–क्षेत्रकीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी पहल' (BIMSTEC) का एक संस्थापक सदस्य है।
1999	बांग्लादेश–चीन–भारत–म्यांमार आर्थिक गलियारे (BCIM) का शुभारंभ।
2001	भारत एडीबी के दक्षिण एशिया उप–क्षेत्रीय आर्थिक कार्यक्रम (SASEC) में सम्मिलित हुआ। 2016-25 परिचालन योजना, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ बहु–विधा परिवहन संपर्क पर केंद्रित है।
2001	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग (DoNER) निर्मित किया गया, 2004 में मंत्रालय के रुप में उन्नत किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र विज़न–2020, पड़ोसी देशों के साथ संपर्क को प्राथमिकता देता है।
2002	भारत–म्यांमार–थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग (IMT) की घोषणा, जो निर्माणाधीन है।
2007	दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (SAU) की स्थापना के लिए सार्क (SAARC) समझौता किया, जो 2010 में नई दिल्ली में अपना सत्र आरम्भ करता है।
2009	भारत और बांग्लादेश, 'विकास हेतु सहयोग पर फ्रेमवर्क समझौते' की घोषणा करते हैं जो संबंद्धता और उप–क्षेत्रीय सहयोग पर केंद्रित है।
2011	भारत, मालदीव और श्रीलंका अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के मध्य एक त्रिपक्षीय वार्ता आरम्भ करते हैं।
2013	बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल संबंद्धता और पारगमन, जल संसाधन प्रबंधन और विद्युत / जल विद्युत पर बीबीआईएन (BBIN) कार्य समूहों का निर्माण करते हैं। 2015 में बीबीआईएन (BBIN) मोटर वाहन समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।
2014	मोदी ने पडोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति की घोषणा की, सभी सार्क देशों के नेताओं को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया और काठमांडू में 18 वें सार्क सम्मेलन में भाग लिया।
2015	भारत, एशियाई अवसंरचना विकास बैंक (AIIB) में सम्मिलित हो गया, जिसका वह सबसे बड़ा उधारकर्ता बन गया।
2015	भारत विदेशों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं हेतु बोली लगाने वाली निजी और सार्वजनिक कंपनियों का समर्थन करने के लिए रियायती वित्त योजना (CFS) को अपनाता है।
2015	भारत और जापान ने "निशुल्क और मुक्त भारत प्रशांत क्षेत्र", क्षेत्रीय संबंद्धता और तीसरे देशों में संयुक्त परियोजनाओं पर केंद्रित विज़न–2025 को अपनाया।
2017	संयुक्त राज्य अमेरिका के मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन (MCC) ने, भारत और बांग्लादेश के साथ विद्युत संबंद्धता सहित नेपाल में अपने पहले दक्षिण एशियाई कॉम्पैक्ट के लिए 500 मिलियन अमरीकी डालर की मंजूरी दी।
2017	भारत चीन में 2017 बेल्ट एंड रोड फ्रोरम में सम्मिलित नहीं होता है, इसकी पारदर्शिता और स्थिरता पर चिंता व्यक्त करता है। 2018 के बाद भारत–चीन संबंधों में सामान्यीकरण के बावजूद दिल्ली बीजिंग के "भारत चीन +1" त्रिपक्षीय परियोजनाओं के लिए प्रस्तावों के बारे में अनिच्छुक रहता है।
2018	चौथा बिम्सटेक (BIMSTEC) शिखर सम्मेलन काठमांडू में आयोजित किया जाता है, जिसमें संगठनात्मक सुधारों हेतु तथा बंगाल की खाड़ी में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नया घोषणा पत्र है।
2019	भूटान ने डिजिटल संबंद्धता को बढ़ाने के लिए 2017 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए साउथ एशियन सैटेलाइट के लिए रिसीविंग स्टेशन का उद्घाटन किया। भारत और नेपाल के मध्य दक्षिण एशिया की पहली सीमा–पार तेल पाइपलाइन का उद्घाटन। चार दशकों से अधिक समय के बाद, भारत और जाफना के मध्य उत्तरी श्रीलंका में उड़ान संपर्क बहाल हुआ। बांग्लादेश पूर्वोत्तर राज्यों में भारतीय पारगमन की पहुंच से सहमत हुआ।

दशकों के ठहराव के बाद, नीति–निर्धारण प्रणालियां अत्यंत तात्कालिकता क्षेत्रीय संबंद्धता विकसित करने के लिए जागृत की गई हैं। विडंबना यह है कि, अब जबकि भारत क्षेत्रीय संबंद्धता पहलों को लागू करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है, लेकिन इसके लिए अनिवार्य आवश्यकताएँ ऊंची तय की गई हैं जिसके कारण अनेक सीमाएं और चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति को पहले नीचे सूचीबद्ध सात चुनौतियों का समाधान करना होगा।

1. भारतीय संबंद्धता रणनीति को अनिवार्य रूप से नए शोध, ज्ञान और पड़ोसी देशों और विशिष्ट क्षेत्रकों पर डेटा के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर संपन्न किया जाना चाहिए। इसके लिए क्षेत्रीय और सीमा पार अध्ययनों में निवेश करने की आवश्यकता होगी, चाहे वह नृवंश विज्ञान संबंधी सीमा समुदायों या पड़ोसी देशों में विनियामक ढांचों, भूमि अधिग्रहण, डेटा गोपनीयता या अंतर्देशीय जलमार्ग नेविगेशन का सर्वेक्षण करना हो।

2. भारतीय संबंद्धता रणनीति को, क्षेत्रीय मंत्रालयों (जैसे विद्युत या शिपिंग), राज्य सरकारों, और राजनीतिक दलों (जैसे नेपाल के लिए उत्तर प्रदेश, या म्यांमार के लिए मिजोरम में), नागरिक समाज के प्रतिनिधियों (जैसे विश्वविद्यालयों या पर्यावरण कार्यकर्ताओं), और साथ ही बहुपक्षीय संगठनों (उदाहरण के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक [AIIB] या (ADB) जैसे नए हितधारकों के साथ समन्वय में लागू करना होगा।

3. भारतीय संबंद्धता रणनीति को भारत के विशिष्ट ध्यान आकर्षित करने वाले बिंदुओं को प्राथमिकता देनी होगी और छोटी, कार्रवाई योग्य पहलों को लागू करना होगा। एक ही समय में सब कुछ संबद्ध करने और एक वृहत परिदृश्य प्राप्त करने का प्रयास करना प्रशंसनीय महत्वाकांक्षा है लेकिन इस आपाधापी में प्राय: वास्तविक तथा आधारभूत लक्ष्य से ध्यान हट जाता है। भारत को इसके तुलनात्मक लाभ को बढ़ाने वाले विशिष्ट क्षेत्रों और परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। भौतिक अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तपोषण करने के विषय में चीन के साथ आंख मूंदकर प्रतिस्पर्धा करने के स्थान पर दिल्ली को संबंद्धता के मृदु आयामों जैसे क्षमता निर्माण इत्यादि का विकास करने में अपेक्षाकृत अधिक रुचि लेनी चाहिए। इससे बेहतर अनुक्रमण तथा उत्प्रेरक परियोजनाओं की प्रभावशीलता संभव होगी जो भारत और उसके पड़ोसियों के मध्य दीर्घकालिक निर्भरता और तालमेल उत्पन्न करती है।

4. भारतीय संबंद्धता रणनीति को सीमा पार अवसंरचना में सभी प्रकार के निवेश के अतिरिक्त आर्थिक खुलापन भी आवश्यक होगा। जब तक व्यापार तथा गतिशीलता के अन्य रूपों के लिए बाधाएं बनी रहती हैं तब तक समुद्री पत्तन, सड़क, रेलवे और हवाई अड्डे बेकार रहेंगे। दक्षिण एशियाई आर्थिक संघ के प्रति परस्पर आर्थिक निर्भरता (यदि आवश्यक हो तो पाकिस्तान के बिना), क्षेत्रीय एकीकरण प्राप्त करने की भारत की क्षमता का आकलन करने की कसौटी होगा।

5. भारतीय संबंद्धता रणनीति, अस्वीकार करने के स्थान पर स्वीकार करने की होनी होगी। नीति निर्माण के संकीर्ण क्षितिज कभी–कभी अभी भी पड़ोस में चीन की 'बेल्ट एंड रोड' (BRI) संबंद्धता पहलों में बाधा डालने के लिए सुरक्षा केंद्रित दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते हैं। दिल्ली को अपना ध्यान केंद्रित किए रहना होगा, और संधारणीय संबंद्धता पहलों के विषय में अधिकाधिक बेहतर तथा तीव्र गति से योगदान करने के लिए तैयार रहना होगा। इसका अर्थ है कि भारत को बीजिंग के साथ खराब संबंद्धता सौदों (तथाकथित ऋण जालों) के कारण वित्तीय दयादान (ख़ैरात) चाहने वाले पड़ोसियों के लिए सुविधाजनक बैंक बनने से भी बचना होगा।

> भौतिक अवसंरचना ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण पर चीन के साथ आंख मूंदकर प्रतिस्पर्धा करने के स्थान दिल्ली को क्षमता निर्माण सहित संबंद्धता के मृदु आयामों पर अपेक्षाकृत अधिक निवेश करना चाहिए।

6. भारतीय संबंद्धता रणनीति को पड़ोसी देशों की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलताओं पर विचार करना होगा। यह भूटान के द्वारा बीबीइन मोटर वाहन समझौते के कार्यान्वयन में देरी किए जाने का एक कारण है। क्षेत्रीय संबंद्धता दिल्ली के लिए सहमति योग्य और तार्किक प्रस्ताव की प्रकार प्रतीत हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि अन्य राजधानियों को इस प्रकार की वांछनीयता हमेशा अनुभव न होती हो जो भारत पर निर्भर होने में चिंतित अनुभव करती हों और इस प्रकार क्षेत्र से परे, विशेष रूप से चीन के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए अधिक उत्सुक रहती हों।

7. अंतत:, भारतीय संबंद्धता रणनीति को इस क्षेत्र में सांस्कृतिक एप्ता या एक समानता पर अत्यधिक जोर देने से बचना चाहिए। पूरे दक्षिण एशिया में अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक आई. पी. खोसला अपनी चेतावनीपूर्ण टिप्पणी में कहते हैं कि, ''भारत के पड़ोसियों को उन प्रस्तावों का समर्थन करना मुश्किल लगता है जो किसी भी अर्थ में पूर्ववर्ती ऐतिहासिक युगों की एकता को पुन: स्थापित करने का संकेत देते हों।[39] कई घरेलू भारतीय क्षेत्रों के लिए भी, सीमापार अधिकाधिक गतिशीलता और प्रवास के साथ संबंद्धता की तुलना करना सदैव लाभदायक नहीं हो सकता।

39 I.P. Khosla (2014). How neighbours converge: The politics and economics of regionalism. Konark Publishers, p. 109.

'संबंध': क्षेत्रीय संबंद्धता पहल

2003 में सार्क मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में बोलते हुए, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई वाजपेयी ने क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ाने में नागरिक समाज और गैर–सरकारी प्रतिभागियों के महत्व पर जोर दिया:

"किसी भी राजनीतिक प्रबोधन की तुलना में, सूचना, समाचारों, विचारों और दृष्टिकोणों का मुक्त प्रवाह क्षेत्रीय सहयोग हेतु अधिक योगदान कर सकता है। हमारे क्षेत्र के लोगों के स्तर पर मित्रता और सहयोग हेतु अत्यधिक आकांक्षा विद्यमान है। राजनेताओं के रूप में हमें इस मांग के प्रति अनुक्रिया करनी चाहिए।"[40]

आज के समय में, पहले की किसी भी समय की तुलना में क्षेत्रीय सहयोग के लिए मांग अत्यधिक है और साथ ही आज से 10 या 20 वर्ष पहले की तुलना में अवसर अधिक सार्थक हैं। भारत को इस विषय में समुचित सूचना के आधार पर अपने विकल्प चयन करने चाहिए कि इस क्षेत्र में क्यों, कहां और किन शर्तों पर संबंद्धता महत्व रखती है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभावी भारतीय संबंद्धता रणनीति, विशेषज्ञ ज्ञान, अनुसंधान, तथा क्षेत्र के विषय में आंकड़ों की उपलब्धता पर निर्भर होगी। 2008 में भारतीय राजनयिक प्रशिक्षुओं के एक नए बैच से बात करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने यह स्वीकार किया कि, ''हमें अपने पड़ोस में होने वाली गतिविधियों के विषय में पर्याप्त जानकारी नहीं रहती है'' और यह कि ''इन देशों के विषय में हमारी विचारधारा अत्यधिक रूप से पश्चिमी धारणाओं से प्रभावित रहती है।''[41] आज से 10 वर्ष से अधिक पहले, स्थितियां कहीं अधिक बेहतर थीं। चीन के कारण भारत के पड़ोसी देशों में अब अन्य देशों की रुचि निरंतर बढ़ती जा रही है और विश्वविद्यालयों, थिंक टैंक, और राजनयिक और सैन्य प्रशिक्षण संस्थानों में दक्षिण एशियाई अध्ययनों का उपेक्षित क्षेत्र धीरे धीरे पुनरुद्धार का अनुभव कर रहा है। लेकिन आवश्यकता कहीं अधिक है।

ब्रूकिंग्स इंडिया की क्षेत्रीय संबंद्धता पहल, 'संबंध', क्षेत्रीय संबंद्धता बढ़ाने के लिए अधिक रणनीतिक भारतीय दृष्टिकोण का समर्थन करके इन मांगों के समाधान का प्रयास करती है। 'संबंध' का अनुसंधान संबंद्धता पहलों के मध्य तारतम्य स्थापित करने, प्राथमिकताओं की पहचान करने, कार्यान्वयन की निगरानी करने और प्रभावशीलता में वृद्धि करने हेतु नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों को समर्थन करने का प्रयास करता है।

भारत के क्षेत्रीय पड़ोस पर ध्यान केंद्रित है, जो रणनीतिक मंडल सिद्धांत का पहला संकेंद्री वलय है। जब तक देश पहले अपनी निकटतम परिधि के देशों के साथ संपर्क स्थापित नहीं करता तब तक, व्यापक खाड़ी क्षेत्र, हिंद महासागर, या दक्षिण पूर्व एशिया और भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत की वैश्विक प्राथमिकताओं का लड़खड़ाना तय है। इस भौगोलिक परिसीमन से परे 'संबंध' निम्नलिखित पांच मार्गदर्शक सिद्धांतों से प्रेरित है:

1. संबंध' की परिधि संबंद्धता की समग्र समझ को अपनाती है। यदि भारत को अपने पड़ोसियों के साथ संधारणीय रूप से संपर्क बनाए रखना है, तो इसे केवल व्यापार या भौतिक अवसंरचना से परे अवश्य देखना चाहिए और संबंद्धता के सौम्य आयामों को अपनाना चाहिए। पुल और डेटा लिंक आवश्यक हैं लेकिन भारत के लिए सीमाओं के पार लोगों के मन मस्तिष्क आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसी तरह, अगर भारत रणनीतिक रूप से एकीकरण को आगे बढ़ाना चाहता है तो यह विभिन्न खण्डों में संबंद्धता के बारे में नहीं सोच सकता। यही कारण है कि 'संबंध' आर्थिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणियों में संबंद्धता के 40 से अधिक विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करती है (तालिका 2 देखें)। यह विभिन्न क्षेत्रकों में, विभिन्न कालखण्डों (कुछ समय श्रृंखलाएं 1980 के दशक जितनी पुरानी हैं), साथ ही चीन और अन्य प्रतिभागियों /क्षेत्रों की तुलना में भारत के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए सूचकांक जैसे दृष्टिकोण को संभव करता है।

2. संबंध' की कार्यप्रणाली डेटा उन्मुख है। पूरे क्षेत्र भर की राजनीतिक सीमाओं के आर–पार विभिन्न प्रकार के प्रवाहों के अनुभवजन्य संग्रह, मानसिक चित्रण और विश्लेषण पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। चाहे वह विनिर्मित वस्तुओं, भाषा, हथियारों की बिक्री, पर्यटकों, विद्युत या जल का विषय हो, हम अनुभवजन्य रूप से विभिन्न राजनीतिक सीमाओं

40 PM's inaugural speech at the Third SAARC Information Ministers' Conference (2013, November 11). PMO Archives, Prime Minister's Office. Retrieved from https://archivepmo.nic.in/abv/speech-details.php?nodeid=9261

41 PM's address to IFS Probationary Officers (2018, June 11). PMO Archives, Prime Minister's Office. Retrieved from https://archivepmo.nic.in/drmanmohansingh/speech-details.php?nodeid=666

के आर–पार संबंद्धता का मानचित्रण करते हैं। विदेश विभाग के डैशबोर्ड सहित नई पहलों के बावजूद, भारत सरकार अभी भी डेटा को एकत्रित करने, निर्मित करने और सुलभ बनाने में उल्लेखनीय चुनौतियों का सामना करती है, जिनमें से सभी समुचित जानकारी के आधार पर विश्लेषण करने और नीति निर्माण के लिए निरंतर अधिकाधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। 'संबंध' मौजूदा डेटा समुच्चय को, "व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने" और अन्य मामलों में पूरी प्रकार से नए डेटा समुच्चय का निर्माण में सहायता करता है, जिसे सार्वजनिक किया जाएगा।

3. संबंध' का माध्यम क्षमता निर्माण अर्थात दक्षिण एशिया पर केंद्रित विद्वानों की एक नई पीढ़ी को प्रशिक्षण प्रदान करने की दिशा में प्रयासरत है। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में नाटकीय रूप से परिवर्तन हुए हैं और भारत को अपने पड़ोसियों के साथ रचनात्मक रूप से संलग्न होने के लिए नए दृष्टिकोणों की आवश्यकता है। अनेक विषयों की जानकारी रखने वाले भू–रणनीतिक विशेषज्ञों के स्थान पर दिल्ली को डोमेन विशेषज्ञों की आवश्यकता है जो दक्षिण एशिया में आधिपत्य शक्ति के रूप में भारत की पारंपरिक भूमिका को पुनः साकार करने के लिए सुसज्जित हों। हमारे कई नीति–संक्षिप्त सह युवा विद्वानों और प्रशिक्षुओं द्वारा मिलजुल कर लिखे जाते हैं जिन्हें एक विशिष्ट संबंद्धता संकेतक पर गहन अनुसंधान करने के लिए प्रशिक्षित और समर्थित किया जाता है। हम विभिन्न विषयों के तकनीकी डोमेन विशेषज्ञों और सेवानिवृत्त अभ्यासकर्ताओं के साथ मिलकर काम करते हैं जो हमारे लेखकों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और कार्य की सहकर्मी समीक्षा करते हैं।

4. भारत और पड़ोसी देशों में स्थापित विशेषज्ञों और अन्य शोध संस्थानों के साथ एक नेटवर्क में कार्य करते हुए 'संबंध' का दृष्टिकोण सहयोगात्मक और अंतःविषयक है। हमारे संबंद्धता संकेतक क्षेत्रों की विस्तृत श्रृंखला पर विस्तारित हैं, जिनमें से कुछ पर पहले से ही विशेषज्ञों और अन्य विशेष कार्यक्रमों द्वारा गहराई से शोध किया गया है। उदाहरण के लिए व्यापार या विद्युत पर, साहित्य की एक विस्तृत श्रृंखला मौजूद है जिसमें थोड़ा ही जोड़ा जा सकता है; इन मामलों में हमारे नीति–संक्षिप्त एक सारांश प्रदान करते हैं और इस प्रकार के काम का उल्लेख करते हैं, अधिक से अधिक नीति निर्माताओं के लिए जटिल मुद्दों का अनुवाद करने में सहायता करते हैं। अन्य क्षेत्रों में, हमारे नीति–संक्षिप्त अभी तक खोजे नहीं गए संबंद्धता संकेतक की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं और गहन अनुसंधान कार्यक्रम के लिए आधार तैयार करते हैं। हम दक्षिण एशिया पर शोधकर्ताओं के एक सहयोगी भारतीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का निर्माण करने के लिए सहकर्मियों और अभ्यासकर्ताओं के सहयोग से 'संबंध' को विस्तारित करने की आशा करते हैं।

5. अंततः, 'संबंध' का परिप्रेक्ष्य भारतीय और नीति उन्मुख है। यद्यपि यह पड़ोसी देशों की संबंद्धता के मानचित्रण, और सहयोग और एकीकरण पर एक क्षेत्रीय बहस के लिए भी योगदान देता है, हमारा प्राथमिक लक्ष्य सरकारी, निजी और नागरिक समाज के हितधारकों से इनपुट प्राप्त कर भारतीय संबंद्धता रणनीति में योगदान देना है। यही कारण है कि परियोजना का पहला चरण संचार के हमारे प्राथमिक माध्यम के रूप में नीति–संक्षिप्तों का उपयोग करता है: जिन्हें 3,000 से कम शब्दों में सार संक्षेपित कर मानसिक चित्रण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक संक्षिप्त गैर विशेषज्ञ दर्शक के लिए सुलभ होता है और भारत सरकार द्वारा क्षेत्र के लिए विकसित किए जा रहे तात्कालिक रूप से नितांत आवश्यक ''वृहत परिदृश्य'' में योगदान करता है।

तालिका 2:
संबंद्धता का मानचित्रण: संबंध की श्रेणियां एवं नमूना संकेतक

आर्थिक
व्यापार
विदेशी निवेश
मौद्रिक और वित्तीय
उड़ानें और हवाई मार्ग
समुद्र और भूमि समुद्री पत्तन (ICPs)
नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग
डिजिटल, उपग्रह और दूरसंचार
विद्युत
पर्यावरण
नदियां और बेसिन
मत्स्य पालन
समुद्र अधस्तल
वायु प्रदूषण
प्राकृतिक अभयारण्य
राजनीतिक
आधिकारिक यात्राएं (प्रधानमंत्रियों, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों आदि की)
क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण (भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग आदि)
विकास सहायता
राजनयिक मिशन
क्षेत्रीय संस्थाएं
तकनीकी कन्वेंशन
संयुक्त राष्ट्र के मतदान पैटर्न
समुद्री सीमाएं
सुरक्षा
शस्त्र हस्तांतरण
सैन्य अभ्यास
रक्षा आदान–प्रदान और प्रशिक्षण
सैन्य तैनाती और रक्षा सहचारी
सीमा बाड़ और प्रबंधन
मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन
सामाजिक सांस्कृतिक
छात्र
पर्यटक
प्रवास
भाषाएं
सांस्कृतिक केंद्र, आदान–प्रदान
मीडिया कवरेज
विश्वविद्यालय और अनुसंधान

लेखक के बारे में

कॉन्स्टेंटिनो जेवियर
अध्येता, विदेश नीति

डॉ कॉन्स्टेंटिनो जेवियर ब्रुकिंग्स इंडिया में, नई दिल्ली में, विदेश नीति अध्ययन में अध्येता हैं जहां वह क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत पर कार्य करते हैं और 'संबंध' पहल का नेतृत्व करते हैं। उनका शोध दक्षिण एशिया, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्रों में संबंद्धता, सुरक्षा और लोकतंत्र के मध्य बदलते गठजोड़ की जांच करता है।

cxavier@brookingsindia.org

SAMBANDH
Regional Connectivity Initiative

'संबंध': क्षेत्रीय संबंद्धता पहल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इत्यादि पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों का मानचित्रण करने के लिए डेटा–चालित अनुसंधान आयोजित करती है। संबंद्धता की समग्र समझ से प्रेरित होकर 'संबंध' सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यावरण, राजनीतिक और सुरक्षा संकेतकों में भारत के क्षेत्रीय एकीकरण का सर्वेक्षण करती है। विद्वानों और अभ्यासकर्ताओं से सहयोगात्मक जानकारी के आधार पर, नीति–संक्षिप्तों की यह श्रृंखला, दक्षिण एशिया और भारत–प्रशांत क्षेत्र के साथ भारत का संपर्क पुनः स्थापित करने में रुचि रखने वाले नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों के लिए अनुभवजन्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

9 788194 196372 >

ब्रूकिंग्स संस्थान भारत केन्द्र
नंबर 6, द्वितीय तल, डॉ जोस पी रिज़ल मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली – 110021

@BrookingsIndia   Brookings.India   Brookings India   www.brookings.in